Film Festivals from the National Film Development Corporation in view of growing criticism;

(b) whether the views of film makers, film critics and representatives of film Industry are considered necessary before taking a final decision in the matter;

(c) what are the findings of Ashok Mitra Committee; and

(d) whether the transfer of this Directorate to the Ministry has been opposed by Shri Ashok Mitra subsequently, if so, the final decision taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) No, Sir.

(b) The decision was taken after due delebration and taking into account various points of view in this regard.

(c) The main findings of Dr. Ashok Mitra Committee about the functioning of National Film Development Corporation (NFDC) are given in the Annexure. [*See* Appendix CXLVI, Annexure No. 51].

(d) Government have not received any communication from Dr. Ashok Mitra opposing the transfer of the Directorate of Film Festivals from the National Film Development Corporation.

खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात

1238. **श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों के स्थान पर खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में तिलहनों की पिराई करके इनसे तेल निकालने के लिए चल रही तेल मिलों आदि को उनकी क्षमता के अनुरूप तिलहन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश में तिलहनों के उत्पादन की मात्रा को देखते हुए, इन मिलों को तिलहनों से तेल निकालने की क्षमता क्या है और क्या सरकार तेल मिलों को पूरा माल देने के लिए खाद्य तेलों की अपेक्षा तिलहनों का आयात करने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पिराई की कुल क्षमता लगभग 260–270 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि तिलहनों का उत्पादन क्रमश: 1984–85 में 129.5 लाख मीटरी टन, 1985–86 में 100.3 लाख मीटरी टन तथा 1986–87 में 114 लाख मीटरी टन रहा ।

कृषि पर आधारित उद्योगों की क्षमता का कम उपयोग होना एक आम बात है । तिलहन की पिराई वाले उद्योग में क्षमता का कम उपयोग होने के कई कारण हैं जिनमें पुरानी संयंत्र मशीनरी को आधुनिक बनाने की कोशिश न होना, उच्च ऊर्जा किस्म का न होना जिसके परिणामस्वरूप मिलों को अधिक जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, खास कर सूखे के वर्षों में शामिल हैं ।

सरकार आम तौर पर खाद्य-तेलों की अपेक्षाओं, तिलहनों के आयात संबंधी निश्चित और बदलती रहने वाली अपेक्षाओं तथा मिलने वाले तेलों को प्राप्त करने और वितरित करने में संभार तन्त्र संबंधी और प्रशासनिक समस्याओं जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए तिलहनों के आयात के पक्ष में नहीं है । लेकिन यह प्रस्ताव रखा गया कि सूखे की स्थिति के कारण राष्ट्रीय तिलहन विकास बोर्ड के जरिए केवल सहायता के आधार पर 5 लाख मीटरी टन तिलहनों का आयात किया जाये । वैसे, वास्तविक आयात सहायता की उपलब्धता तथा अन्य विचारणीय बातों पर निर्भर करेगा ।